RAJYA SABHA

Thursday, the 30th August, 2007/8 Bhadrapada, 1929 (Saka)

The House met at eleven of the clock,
[MR. CHAIRMAN in the Chair.]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Eco Mark certification

*241. SHRI HARISH RAWAT:††
SHRI SANTOSH BAGRODIA:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the number of products that have been identified for Eco Mark since 1991;

(b) the basis on which such Eco Mark certification is given; and

(c) the steps taken to popularize the Eco Mark among producers and customers?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI NAMO NARAIN MEENA): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The Government of India has notified sixteen product categories under the Eco Mark Scheme.

(b) Environmental criteria for each product category are notified by the Central Government and later on translated into Indian Standards by the Bureau of Indian Standards (BIS). Products are examined in terms of the following main environmental impacts:–

(i) that they have substantially less potential for pollution than other comparable products in production, usage and disposal.

(ii) that they are recycled, recyclable, made from recycled products or bio-degradable, where comparable products are not;

---

†† The question was actually asked on the floor of the House by Shri Harish Rawat.

(iii) that they make significant contribution to saving non-recyclable resources including non-renewable energy sources and natural resources compared with comparable products;

(iv) that the product must contribute to a reduction of the adverse primary criteria which has the highest environmental impact associated with the use of the product, and which will be specifically set for each of the product categories.

In determining the product specific requirements for setting eco-criteria, the following are taken into account:

(i) *production process including source of raw materials;*

(ii) use of natural resources;

(iii) likely impact on the environment;

(iv) energy conservation in the production of the product;

(v) effect and extent of waste arising from the production process;

(vi) disposal of the product and its container;

(vii) utilization of "Waste" and recycled materials;

(viii) suitability for recycling or packaging; and

(ix) biodegradability

(c) The steps taken to popularize the Eco Mark among manufacturers and consumers include the following:–

(i) Conduct of consumer awareness programme and industry awareness programme including workshops and studies on Eco Mark.

(ii) Financial support to consumer organizations for comparative testing of products and dissemination of its findings.

श्री हरीश रावत: सर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी तक ऐसे कितने प्रोडक्ट्स हैं, जो Eco Mark स्कीम के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं तथा इस Eco Mark स्कीम का present status क्या है? क्या इसको determine करने के लिए experts की कोई body है?

श्री नमो नारायण मीणा: सर, यह स्कीम भारत सरकार ने 1991 में प्रारंभ की थी और इसमें अब तक 16 categories को नोटिफाई किया गया है। माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि कितने आइटम्स को इसमें कवर किया गया है? इस स्कीम में अब तक 20 Eco Mark licenses पंद्रह कंपनियों को दिए जा चुके हैं, जो तीन product categories में आते हैं - paper, wood substitute and finished leather. सर, इस रिज़ॉल्यूशन के तहत steering committees और दूसरी technical committees हैं। ये steering committees policy formulation का काम करती हैं और technical committees इन प्रोडक्ट्स को approve करती हैं।

श्री हरीश रावत: सर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से यह स्पष्ट है कि 1991 से जो स्कीम ऑपरेशन में है, अभी तक केवल 20 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, जिनको eco friendly mark दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि यह स्कीम लोकप्रिय नहीं हो पाई है। तो इसको लोकप्रिय बनाने के लिए, इसको popularise करने के लिए इनका मंत्रालय क्या कदम उठा रहा है? जो भी कंपनियां इस तरह के प्रोडक्ट्स तैयार करती हैं, उनको क्या इंसेंटिव देने पर विचार कर रहा है?

श्री नमो नारायण मीणा: सर, कुछ हद तक मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि यह स्कीम हमारे देश में इतनी सफल नहीं हो पाई है, जितनी developed और rich countries में हुई है, जैसे जर्मनी, जापान, स्वीडन और कोरिया, जहां बहुत तादाद में लोगों ने अपने प्रोडक्ट्स को green level करवाया और इस तरह का mark लिया है। इसके कुछ वजूहात हैं, जैसे lack of awareness among consumers है। इंडस्ट्री में भी इस तरह की जागरूकता की कमी है और इंसेंटिव्ज़ की भी कमी है। कई दूसरे देशों ने कुछ-कुछ इंसेंटिव भी इस स्कीम को दिया हुआ है और एक सबसे बड़ी बात इस स्कीम के successful होने के लिए यह है कि जो कंज्यूमर होता है, वह हमेशा सस्ती चीज़ को देखता है और eco friendly और eco mark वाले जो भी आइटम्स होंगे, वे दूसरे आइटमों से थोड़े महगें होते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में लोग उनको खरीद नहीं पाते हैं। कुछ इस तरह की बात भी है कि थोड़ा प्रोसीजर भी अपनाना पड़ता है, इसलिए कंपनियां इसमें आ नहीं पाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यह एक ऐसा issue है, environmental issue है, जिसमें सरकार, कंज्यूमर और इंडस्ट्री, सबको सोचना पड़ेगा कि environment सुरक्षित हो, आदमी की health सुरक्षित हो और एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो, जिस पर सब आकर अपनी कुछ न कुछ भागीदारी निभाएं, contribute करें, ताकि urbanisation से, industrialisation से जो हमारा वातावरण खराब हो रहा है, उसमें improvement हो। कुछ स्टेप्स जो लिए गए हैं, उनके बारे में मैंने मेरे रिप्लाई में बताया है। उसके बावजूद भी हमने सेमिनार्स किए हैं। उसमें लोगों के, इंडस्ट्रीज़ से, कंज्यूमर्स से जो सुझाव आए हैं, उसमें इस तरह की बात उन्होंने कही है। इस स्कीम की हमेशा स्ट्रेटजी बदलती रहती है, रिव्यू भी होता रहता है। उसमें लोगों के जो सुझाव आए हैं, उनमें यह कहा है कि लॉंग टर्म और शॉर्ट टर्म मेज़र्स अपनाए जाएं ताकि इसके प्रति अवेयरनेस बढ़े। इंडस्ट्रीज को, सबके सेक्टर्स को इसमें जोड़ा जाना चाहिए। इसके अलावा जो ट्रायल्स होते हैं, टेस्टिंग्स होती हैं, उनकी वाइड पब्लिसिटी की जानी चाहिए। यह भी एक बात आयी है कि इसको रिव्यू किया जाए। इसलिए समय-समय पर इसमें रिव्यू करने की आवश्यकता है, इस संबंध में हमारा रिव्यू अंडर कंसिड्रेशन भी है। गुड प्रेक्टिस गाइडलाइन्स भी जारी होनी चाहिए ताकि लोग उसको ज्यादा से ज्यादा समझ सकें। मैं यह मानकर चलता हूं कि यह अच्छी स्कीम है, इसका ज्यादा प्रचार-प्रसार होना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में इस तरह के इको-मार्क प्रोडक्टस के प्रति लोगों का रुझान बढ़े।

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Sir, since the hon. Minister has just now mentioned that he is willing to review the Scheme, I would like to know whether the hon. Minister would give preference to products in their procurement and also fiscal incentives for their exports. Similarly, I would also like to know from the hon. Minister as to how does the Steering Committee chose a product-category for Eco-Mark Certification and which are the product categories under consideration of the Steering Committee; and does it overlap the mandate given to the Technical Committee and the BIS?

SHRI NAMO NARAIN MEENA: Sir, as far as this Scheme is concerned, I would like to submit that this is a voluntary Scheme. It is not binding, not only in our country, but also throughout the world. The Government does not give any incentive to any industry or product. At the same time, we have only a few countries which are giving incentives in tenders for preferential purchases. No direct incentive is being given.

So far as the functions of the Steering Committee and the Technical Committee are concerned, as I mentioned earlier, the functions of the Steering Committee are to formulate strategies for promotion, future development and improvement of the Scheme. Whereas, the functions of the Technical Committee are to see the item and product concerned from the technical point of view.

SHRI C. PERUMAL: Sir, I would like to know from the hon. Minister whether there is any law for making it compulsory to have eco-mark on certain products. If so, the details of enforcement machinery for detecting and punishing the violators?

SHRI NAMO NARAIN MEENA: Sir, all types of companies approach the Steering Committee for marketing/labelling their products as eco-friendly. And then it goes to the Technical Committee, and finally it goes to the Bureau of Indian Research for giving eco-mark. If any company approaches for Eco-Mark Certification, it will be considered accordingly.

SHRI MATILAL SARKAR: Sir, thank you for allowing me to put a supplementary. Sir, the use of khadi products is dwindling. But, it is a fact that khadi products are eco-friendly. So, I would like to know, through you, from the hon. Minister whether the Government will consider including khadi products under eco-friendly scheme. If so, the details may be given.

SHRI NAMO NARAIN MEENA: Sir, as I have mentioned earlier, this scheme is voluntary and non-binding. The hon. Member wants to know whether the Government is considering or can consider to give some incentives to Khadi. No such proposal is pending with us.

डा०(श्रीमती) नजमा ए० हेपतुल्ला: मैं ऑनरेबल मिनिस्टर से आपके थ्रू पूछना चाहूंगी कि यह जो आपने इको-फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के लिए 16 केटेगरीज आइडेंटिफाइ की हैं, सबसे ज्यादा पौल्यूशन पैकेजिंग मैटीरियल से होता है। तो गवर्नमेंट की क्या स्कीम है कि पॉलिथीन और प्लास्टिक के यूज को डिस्करेज किया जाए। क्या आप कुछ ऐसे इंसेंटिव लोगों को या एन०जी०ओज़० वगैरह को देंगे ताकि वे इसको डिस्करेज करके पैकेजिंग में इको-फ्रेंडली मैटीरियल का यूज ज्यादा होने लगे।

श्री नमो नारायण मीणा: सर, प्रोडक्ट केटेगरीज में पैकेजिंग मेटीरियल और प्लास्टिक प्रोडक्ट को इसमें लिया हुआ है। अभी तक किसी भी कम्पनी ने इसके लिए एप्लाई नहीं किया है, wood substitute, finished leather and paper इसमें किया हुआ है। प्लास्टिक का जहां तक सवाल है, यदि इसका मिसयूज होता है तो बिल्कुल ह्यूमन हैल्थ के लिए और पर्यावरण खराबी के लिए काफी असर पड़ता है और खास करके जहां टूरिस्ट प्लेसेज में हाई एल्टीट्यूड्स में लोग जाते हैं और वहां इसको छोड़कर आते हैं तो इसका गलत असर पड़ता है। कई स्टेट में इसको जगह-जगह पर बंद किया हुआ है। इसके लिए कानून बना हुआ है और कही

बैन किया हुआ है। अगर कोई स्टेट चाहती है तो इसको एक पर्टिकुलर स्थान पर बेन किया जा सकता है। लेकिन साथ ही साथ हमको यह भी देखना पड़ता है कि प्लास्टिक के बहुत सारे यूज हैं और उसका जब तक कोई आल्टरनेटिव नहीं आ जाता, तो एक साथ सबको बंद करना संभव नहीं है। लेकिन मैं इससे सहमत हूं कि फेज़ मैनर में इसके बारे में कदम उठाते रहना चाहिए और जहां-जैहां भी इनसे पर्यावरण खराब होता है या और कोई बात होती है तो इस पर बैन लगना चाहिए।

Vanishing brides and abandoned grooms abroad

*242. MS. SUSHILA TIRIYA: Will the Minister of OVERSEAS INDIAN AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the number of cases of vanishing brides and abandoned grooms abroad has increased in the recent past;

(b) whether Government had formed a Committee in this regard; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS (SHRI VAYALAR RAVI): (a) to (e) A statement is laid on the Table of the House.

(a) to (c) The Ministry was created in May 2004 and since then the problem of desertion of Indian women by their overseas Indian husbands is being monitored. The complaints received regarding Indian women deserted/divorced by their overseas Indian husbands for the last 3 years is as follows:

Year 2005	—	19
Year 2006	—	65
Year 2007 (till August)	—	89

Complaints are also received in Ministry of Women and Child Development, NCW and NHRC. Thus, precise data on the number of cases of vanishing brides and abandoned grooms abroad is not available. An inter-Ministerial Committee has been constituted to study the problems arising in marriages with overseas Indians and to suggest ways to address them.

MS. SUSHILA TIRIYA: Sir, the Minister has given data from 2005 to 2007. The divorce rate in overseas is increasing. No doubt, the cases of brides vanishing abroad, as well as, within India are also increasing. There are foeticides, murders, dowry deaths, etc. So, my question to the hon. Minister is: May I know whether the Government has set up any judicial forum or any counselling centres, in India, to provide legal assistance in India to avoid excessive litigation expenses, and to provide them counselling?

SHRI VAYALAR RAVI: Sir, the Ministry has taken certain initiatives. One of the initiatives is that the Ministry has constituted an inter-Ministerial Committee on the basis of the National Commission for Women's report. The Committee includes the Ministry of External Affairs, the Ministry of Overseas Indian Affairs, the Ministry of Home Affairs, and the Ministry of Law. Besides, the State Governments, the